1	2	3	4
2 अमो० सलफेट	1972–73	..	
	1973–74	35 00 से 45 30	एफ ओ बी बल्क
3 डी ए पी	1972–73	92 00 से 104 50	एफ गो ओ बी बल्क
	1973–74	112 75 से 117.25	एफ ओ बी बल्क
4 एम ओ पी	1972–73	सी डालर 33 00 से सी डालर 34 81	एफओ बी बल्क
	1973–74	सी डालर 42 50 से सी डालर 43 54	एफ ओ बी बल्क
5 ए एन सी	1972–73	66 00 से 80 40	एफ ओ बी जूट थैले
		66 40	एफ ओ बी बल्क
	1973–74	110 80	एफ ओ बी जूट थैले
		92 32	एफ ओ बी बल्क
6 सी ए एन	1972–73	39 50 से 40 75	एफ ओ बी थैला बन्द
		67 50 से 74 40	एफ ओ बी थैला बन्द
7 एन पी के	1972–73		
15 15 15		62 39 से 69 70	एफ ओ बी बल्क
10 26 26		65 90	एफ ओ बी बल्क
12 32 16		66 90 से 91 93	एफ ओ बी बल्क
	1973–74		
15 15 15		86 29 से 93 91	एफ ओ बी बल्क
11 11 11		103 28	एफ ओ बी पी पी बैग
17 8)		146 30	एफ ओ बी पी पी बैग
8 एम ओ पी	1972–73	61 00	एफ ओ बी थैला बन्द
	1973–74	83 53	एफ ओ बी थैला बन्द
9 एम ए पी	1972–73	96 00	एफ ओ बी बल्क
10 ए एस एन	1973–74	75 90	एफ ओ बी थैला बन्द

टिप्पणी —ऊपर दी हुई कीमतें ठेके के अनुसार है। कुछ मामलों में कीमतों में वृद्धि की अनुमति दी गई है। जिसे इन कीमतों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

Scheme of Zonal Reciprocal Agreement for operation of Goods Vehicles in Northern, Eastern and Central Zones

403. **SHRI ARVIND M. PATEL:** Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the question of introducing the scheme of Zonal Reciprocal Agreement for the operation of goods vehicles in the Northern, Eastern and Central Zones similar to the schemes introduced in the Southern and Western Zones has been considered with the respective State Governments; and

(b) if so, when the schemes will come into operation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT: (SHRI H. M. TRIVEDI): (a). The Northern Zone Agreement for goods vehicles, comprising the States/Union Territories of J & K, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Himachal Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, has already been signed and executed by the State Governments and Union Administration concerned, The Reciprocal Agreements in respect of the Eastern and Central Zone Permit Schemes for goods vehicles are being processed with the State Governments concerned.

(b) The Northern Zone Permit Scheme has already come into operation with effect from 1st January, 1974. The other two Schemes are expected to be finalised as soon as the legal formalities as required under the Motor Vehicles Act, 1939 are completed by the State Governments concerned.

'हूंजा' रियासत को पाकिस्तान में मिलाकर अन्तराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

404. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :** **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपने उत्तर में स्थित 'हूंजा' रियासत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान द्वारा किया गया यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विपिनपालदास) (क) 24 सितम्बर, 1974 के पाकिस्तान रेडियो के प्रसारण के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने हूंजा राज्य के पृथक् अस्तित्व को समाप्त कर दिया है और इसके प्रशासन को जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों के साथ मिला दिया है जिन पर पाकिस्तान का अवैध अधिकार है ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान सरकार की इस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर के एक उत्तरी प्रदेश की स्थिति में महत्वपूर्ण एवं इकतरफा परिवर्तन हुआ है जिसका उसे कोई अधिकार या स्वीकृति नहीं और इसलिए उसकी यह कार्रवाई अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत अवैध कार्रवाई है । पाकिस्तान सरकार की यह कार्रवाई शिमला समझौता के पैरा 1 (ii) का उल्लंघन भी है । इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जा चुका है ।

Super Tanker Berth at Cochin

405. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the project report prepared by M/s. Engineers India Ltd., for the super tanker berth at Cochin and approved by the Cochin Port Trust has been received by Government;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) whether Government have taken a final decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M. TRIVEDI): (a) Yes, Sir.

(b) The salient features of the Project are as follows:

(i) The facilities are to be provided for tankers of 80,000 DWT having a draught of 40/-. Provision has also been made for receiving oil tankers upto, 1,15,000 DWT in future. According to the scheme, the inner channel after crossing the Cochin gut is taken northwards into the water-way between the Bolghatty and Wallarpat Islands. The oil berth will be located on the Western side of the new channel thus created.